बारिश के ट्रायल में ही व्यवस्था फेल

भले ही अभी चिलचिलाती तपिश है। लेकिन बारिश भी थोड़े-थोड़े समय पर शहरों की तैयारी का ट्रायल ले रही है। इसमें शहरों की तैयारी के व्यवस्था के लीकेज खुल गए हैं। अभी भी कुछ वक्त है सरकारी एजेंसियां चुस्ती से मानसून से पूर्व इंतजाम कर लें। नालों की सफाई, सड़कों व फ्लाईओवर पर पानी निकासी के द्वारों को दुरुस्त कर लें। अब तक के अनुभव में विफल प्रशासन और परेशान जन जन वाले ही हालात रहे हैं। कहां-कहां है चूक, क्यों नहीं होती है सफाई यही है आज का मुद्दा :

प्लान तो तैयार रखे हैं, एक्शन में आने की जरूरत है

आरजी गुप्ता
पूर्व योजना आयुक्त, दिल्ली विकास प्राधिकरण

कोई एक वजह नहीं है मानसून में होने वाले जल भराव की। अनेक कारण उत्तरदायी हैं। सबसे बड़ा कारण तो लापरवाही ही है। डीडीए एक्ट के सेक्शन आठ के मुताबिक अधिकृत तौर पर दिल्ली 18 जोन में बंटी हुई है। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, जे, के-1, के-2, एल, एम, एन, ओ, पी-1, पी-2। हर जोन का अलग प्लान भी बना हुआ है। लेकिन उसे क्रियान्वित नहीं किया जा रहा। इन अधिकृत जोन से इतर अनधिकृत क्षेत्र अधिक बड़ा हो गया है। कहीं कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है।

बरसाती पानी की निकासी आवश्यक है, लेकिन दिल्ली में वह भी चरमरा सी गई है। किसी जमाने में यहां 617 जोहड़ होते थे। आज इन 617 जोहड़ों में से या तो ज्यादातर खत्म हो गए हैं या सूख गए हैं। यह जोहड़ भी बडे पैमाने पर वर्षा जल का संचयन कर लेते थे और भूजल स्तर में सुधार का कारक भी बनते थे। दिल्ली एनसीआर में कई नहरें-नदियां हैं। मसलन, यमुना, अपर यमुना कैनाल, ईस्ट यमुना कैनाल, गुरुग्राम कैनाल, आगरा कैनाल, हरनंदी (हिंडन) नदी इत्यादि। लेकिन इनकी भी कभी सफाई नहीं की जाती। ऐसे में यह नहरें-नदियां भी वर्षा के जल को नहीं समेट पाती।

वर्तमान में यमुना में 22 नालों का गंद गिर रहा है। यह भी कम चिंताजनक नहीं है। 1979 से 1981 के दौरान जब मैं डीडीए में सेवारत था तो विशेषज्ञ समिति ने यमुना में एक नया बैराज बनाने का सुझाव दिया था। अगर यह बन जाता तो निस्संदेह वर्षा जल संचयन का बड़ा स्त्रोत होता। लेकिन वह भी आज तक नहीं बन पाया।

देखिए, अगर शहर में जल भराव रोकना है तो सर्विस रोड पर किसी भी तरह के अवैध निर्माण को खत्म करना होगा। बरसाती पानी की निकासी के लिए सर्विस लेन एकदम क्लीयर होनी चाहिए। मानसून से पहले नाले-नालियों की सफाई सुनिश्चत करनी चाहिए। टूटी सड़कों की मरम्मत भी बारिश शुरू होने से पहले पूरी हो जानी चाहिए।

एक बड़ी बात यह भी कि ड्रेन और सीवर को आपस में मिलने नहीं देना चाहिए। यह दोनों मिल जाते हैं तो स्थिति बहुत विकट हो जाती है। जब मैं डीडीए में था तो मैंने पूर्वी दिल्ली में तीन नाले बनवाए थे। बाद में इन तीनों नालों को भी सीवरेज की लाइन से मिक्स कर दिया गया। इससे भी समस्या बढ़ती गई। कहने का मतलब यही कि हल हर समस्या का होता है मगर जरूरत है दृढ़ इच्छाशक्ति की। बनी हुई योजनाएं ईमानदारी से लागू करने की और गलत विकसित हो गई चीजों को सिरे से नष्ट करने और नकारने की। विभिन्न सरकारी विभागों में आपसी तालमेल भी बहुत जरूरी है। इसके अभाव में भी समस्या विकराल रूप ले लेती है।

(संजीव गुप्ता से बातचीत पर आधारित) दिल्ली राज्य ब्यूरो

23,931 किलोमीटर दिल्ली की सड़कों की जिम्मेदारी नगर निगम के पास

उनको नालों से गाद और कचरे की सफाई करनी होती है।

60,000 सफाई कर्मचारी तीनों निगम के तहत काम करते हैं

50 करोड़ रुपये हर साल खर्च किए जाते हैं

650 पंप पानी की निकासी के लिए लगाए गए

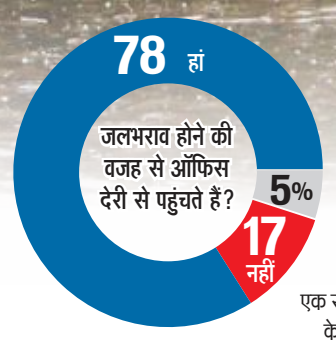

एक संस्था के सर्वे के अनुसार

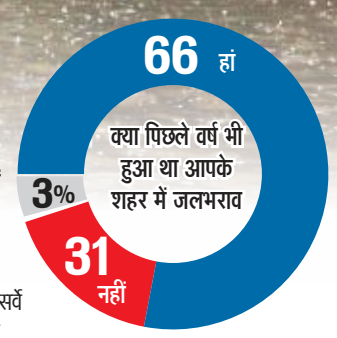

1200 किलोमीटर रोड दिल्ली की पीडब्ल्यूडी के तहत

नालों से गाद निकालना और कचरा हटाना

200 करोड़ रुपये हर साल व्यय किए जाते हैं

530 पानी के पम्प लगाए गए

जनमत

क्या आपके क्षेत्र में जलभराव की स्थिति में विगत कुछ वर्षों में सुधार हुआ है?

क्या जलभराव रोकने के लिए इस बार सरकारी एजेंसियां पहले के मुकाबले कुछ गंभीर दिखाई दे रही हैं?

बिजली नहीं रहने से होती है जलभराव की भयंकर स्थिति

अक्सर बारिश के बाद बिजली चली जाती है और शहर के बूस्टिंग स्टेशन बिजली नहीं होने के कारण बंद रहते हैं जिससे बारिश का पानी तब तक खड़ा रहता है जब तक बूस्टिंग स्टेशन नहीं चलते। फरीदाबाद नगर निगम ने इस बार योजना बनाई है कि प्रत्येक छोटे-बड़े बूस्टिंग स्टेशन पर जनरेटर की व्यवस्था की जाए ताकि बिजली गुल होने पर भी बूस्टिंग पंप चलते रहें। फरीदाबाद में छोटे-बड़े कुल 38 बूस्टिंग स्टेशन हैं। यदि ये सब बूस्टिंग पंप चालू रहें तो बरसात का पानी दो घंटे के अंदर डिस्पोजल संयंत्रों तक भेजा जा सकता है।

जलभराव से तुरंत निबटने के लिए इस बार नगर निगम ने संबंधित जेई के नेतृत्व में स्पेशल टास्क फोर्स बनाई है। इसमें पांच से सात लोग होंगे। एक टीम के पास मूविंग जनरेटर पंप होगा, जिससे ऐसी जगह के जलभराव पर भी काबू पाया जा सकता है जहां से नियमित बूस्टिंग सिस्टम के लिए पंपिंग नहीं हो सकती। बरसात के बाद चिन्हित जलभराव केंद्रों पर इस टास्क फोर्स की नजर रहेगी। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर- 0129-2418400 पर आने वाली शिकायतों को सुनने के लिए तीन अलग टीम तीनों जोन के लिए तैनात रहेंगी।

डीआर भास्कर, मुख्य अभियंता,नगर निगम, फरीदाबाद

फरीदाबाद में जलभराव के कुल प्वाइंट्स

- एनएचपीसी चौक से ग्रीन फील्ड जाने वाले रास्ते में रेलवे अंडरपास
- बड़खल फ्लाईओवर के साथ सर्विस रोड
- ओल्ड फरीदाबाद फ्लाईओवर के साथ सर्विस रोड
- ओल्ड फरीदाबाद से एनआइटी वाले रास्ते में रेलवे अंडरपास
- अजरौंदा फ्लाईओवर के साथ सर्विस रोड
- नीलम फ्लाईओवर से अजरौंदा चौक के दोनों तरफ
- बाटा फ्लाईओवर के साथ सर्विस रोड
- बाटा फ्लाईओवर से राजमार्ग की तरफ रामनगर के सामने
- वाईएमसीए यूनिवर्सिटी के सामने इंदिरा कॉलोनी के सामने
- बल्लभगढ़ फ्लाईओवर के साथ सर्विस रोड
- बल्लभगढ़-सोहना फ्लाईओवर से राजमार्ग की तरफ
- बल्लभगढ़ गुप्ता चौक से महावीर कॉलोनी तक
- बल्लभगढ़-सोहना मार्ग पर
- सेक्टर-16 सर्किट हाउस
- सेक्टर-सात व दस मार्केट
- सेक्टर-नौ व दस विभाज्य मार्ग
- सेक्टर-तीन पुल से राजा नाहर सिंह पैलेस की तरफ
- जवाहर कॉलोनी व नंगला क्षेत्र में
- बल्लभगढ़ मेन बाजार
- सेक्टर-दस मिलन रेस्टोरेंट से सेक्टर-3 पुल तक

फेल हो जाती है यातायात व्यवस्था

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : दिल्ली कहने को तो देश की राजधानी है। लेकिन थोड़ी देर की बारिश से सड़कें नदियों में तब्दील हो जाती हैं और अधिकतर इलाके जलभराव की समस्या से जूझते हैं। जलभराव न सिर्फ लोगों के लिए मुसीबत बनता है, बल्कि अत्याधुनिक दिल्ली यातायात पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती लेकर आता है।

जगह-जगह लगने वाले जाम के बीच यातायात सिग्नल का फेल होना पुलिस के लिए परेशानी का सबब बनता है। मैनुअली ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए 3500 पुलिसकर्मियों को लगाया जाता है, लेकिन जलभराव के आगे यातायात सिस्टम पूरी तरह से फेल रहता है। सालों से चली आ रही इस समस्या का आज तक समाधान नहीं निकल सका।

जलभराव के दौरान यातायात पुलिस के सामने दूसरी बड़ी चुनौती पानी के बीच फंसी लो-फ्लोर बसों, ट्रकों को बाहर निकालना भी होता है। फंसे वाहनों का सिस्टम काम करना बंद कर देता है। जिसके कारण क्रेन के माध्यम से भी वाहन को बाहर निकालना संभव नहीं हो पाता। इस वजह से भी अधिकांश इलाकों में जाम की स्थिति बन जाती है। और यातायात पुलिस बेबस नजर आती है।

इतना ही नहीं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का हेल्पलाइन नंबर भी असहाय हो जाता है। जिस समय जनता को दिल्ली यातायात पुलिस को हेल्पलाइन नंबर की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वह महानगर दूर संचार सेवा की लाइनें पानी में डूबने के कारण ठप हो जाती हैं। एमटीएनएल की लाइन के जरिए ही पुलिस सोशल मीडिया से लोगों को जलभराव के दौरान जाम से बचने के लिए सुझाव देती है।

जलभराव की चुनौती से निपटने के लिए यातायात पुलिस पूरी तरह से तैयार है। कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि आम नागरिकों को कम से कम समस्या हो। जलभराव के दौरान लो-फ्लोर बसों व ट्रकों को बाहर निकालने के लिए क्रेन का इंतजाम रहेगा। साथ ही यातायात संचालित करने के लिए बड़े पैमाने पर यातायात पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी ताकि जाम से लोगों को कम से कम परेशान होना पड़े। परिवहन निगम को पत्र लिखकर क्विक रिएक्शन टीम को जगह-जगह पर उपलब्ध रखने के लिए कहा गया है।

गरिमा भटनागर,
संयुक्त पुलिस आयुक्त यातायात

इन इलाकों में होता है जलभराव

- पंजाबी बाग फ्लाईओवर का अंडरपास
- एम्स फ्लाईओवर से आइएनए मार्केट
- आश्रम चौक • भजनपुरा से खजूरी
- जनपथ • कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन
- धौलाकुआं फ्लाईओवर रिंग रोड
- धौलाकुआं से नारायणा
- मुनरिका सब-वे के पास
- आईटीओ -तिलक मार्ग-सिकंदरा रोड
- जहांगीर पुरी मेट्रो स्टेशन
- लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन
- नेहरू प्लेस • प्रगति मैदान गेट नंबर-7
- मूलचंद फ्लाईओवर के नीचे अंडरपास
- चितरंजन पार्क के क्षेत्र
- निगम बोध घाट • निजामुद्दीन खट्टा
- राजधानी कॉलेज फ्लाईओवर
- शांति पथ सत्य मार्ग व नीति मार्ग
- साउथ एक्सटेंशन पार्ट-1
- वजीराबाद रोड से लोनी रोड

कंट्रोल रूम

- टोडापुर स्थित ट्रैफिक कंट्रोल रूम
- ट्रैफिक कंट्रोल रूम में ही जलभराव से जुड़ी शिकायत आती हैं और फिर यहीं से फायर ब्रिगेड, लोक निर्माण विभाग, विभन्न नगर निगम को जानकारी देकर समस्या पर कार्रवाई का निर्देश दिया जाता है।

समाधान नहीं, सियासत पर जोर

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : बारिश का मौसम दिल्ली वालों को गर्मी और उमस से तो राहत देता है लेकिन जलभराव और जाम की मुसीबत बढ़ जाती है। विगत कई वर्षों से दिल्ली जलभराव से जूझ रही है लेकिन हर बार सिर्फ बारिश के बाद इस समस्या से निजात पर चर्चा होती है। फौरी तौर पर दिलासा देने के लिए योजनाएं भी बनती हैं जो कागजों में सिमटकर रह जाती हैं। नतीजन, हर बार बारिश के बाद दिल्ली जलभराव और जाम में घंटो ठहर जाती है। सड़कों पर वाहन रेंगते हुए गुजरते हैं। घरों और दुकानों में पानी भर जाता है।

दिल्ली में एक दो नहीं 17 सरकारी एजेंसियां हैं जो किसी ना किसी रूप में दिल्ली की सड़कों, नालियों के रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं। हालांकि 98 फीसद दिल्ली की जिम्मेदारी तीनों नगर निगम और लोक निर्माण विभाग की है। पांच राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत आते हैं, अगर यहां जलभराव हो तो यहां सिर्फ एनएचएआइ ही सफाई कर सकता है।

शहर नियोजन के लिए गठित लंबे-चौड़े सरकारी अमले पानी के बहाव में शहरों के ठहरने पर खुद को असहाय पाते हैं। सारा दोष नालों की सफाई नहीं होने और बढ़ती आबादी, घटते संसाधनों पर थोप दिया जाता है। इस बात का जवाब कोई नहीं दे पाता कि नालों की सफाई सालभर क्यों नहीं होती और इसके लिए अप्रैल-मई का इंतजार क्यों होता है। यह सभी जानते हैं कि दिल्ली में बने ढेर सारे पुलों के पास बने अंडरपास और सब-वे हल्की सी बरसात में जलमग्न हो जाते हैं। लेकिन कभी कोई यह जानने का प्रयास नहीं करता कि आखिर निर्माण में कोई कमी है या फिर उसके रखरखाव में। बीते एक दशक में विकास के नाम पर कई फ्लाईओवर बने। सड़कों को सिग्नल फ्री भी बनाया गया लेकिन बावजूद इसके साढ़े तीन सौ से ज्यादा जगहों पर जलभराव होना चिंता की बात है। यह हालात सिर्फ दिल्ली के ही नहीं है एनसीआर के शहरों का भी यही हाल रहता है। विभागों के बीच तालमेल का अभाव रहता है। इसकी एक बानगी सोमवार को यानी 12 जून को उस समय दिखाई दी जब दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की महापौर और निगम नेता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंची। नेताओं ने बड़े नालों की सफाई नहीं होने की शिकायत की।

नालों से निकलने वाली गाद में भी हो गया गोरखधंधा

साल 2014 में आई कैग की रिपोर्ट में नालियों से गाद निकालने के नाम पर चल रहे गोरखधंधे की तरफ इशारा किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि 2010-13 में बाढ़ नियंत्रण विभाग ने 8,30,000 क्यूबिक मीटर गाद नजफगढ़ और ट्रंक वन नालों से निकाली। लेकिन हटाई गई सिर्फ1,00,000 क्यूबिक मीटर बाकी को नाले के पास छोड़ दिया गया। यह कहा गया कि बाकि गाद वापस नाले में चली गई।

कैग की रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि 2001 में दिल्ली मास्टर प्लान के तहत ड्रेनेज का भी मास्टर प्लान बनाना था। वर्ष 2005 में एक कमेटी बनी लेकिन 2012 तक कुछ नहीं हुआ। आइआइटी की रिपोर्ट में सामने आया कि नालों से खराब निकासी और इनकी सफाई न होने से दिल्ली की नालियां जाम हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है और न ही इनकी सफाई अच्छे से होती है जिस कारण जल निकासी नहीं होती और जलभराव होता है।

लापरवाही अब तक नालों की सफाई के लिए टेंडर प्रक्रिया ही नहीं कराई गई, कुछ दिन बाद मानसून आ जाएगा

नहीं है कोई तैयारी, जलभराव से फिर बिगड़ जाएंगे हालात

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम : मानसून नजदीक है लेकिन अभी तक शहर को जलभराव से बचाने के लिए नगर निगम और हुडा ने कोई इंतजाम नहीं किए हैं। नगर निगम अब नालों की सफाई करवाने के लिए टेंडर करेगा, जिसके लिए 21 दिन का समय है। जब तक टेंडर होगा, मानसून की बारिश शुरू हो जाएगी। शहर के ज्यादातर बड़े बरसाती नालों पर कब्जा है और नालों की करीब एक साल से सफाई नहीं की गई है। हर बार मानसून में शहर में जलभराव हो जाता है, जिसके कारण कई दिन तक लोग परेशानी को भुगतते हैं।

बादशाहपुर ड्रेन होता है ओवरफ्लो

बादशाहपुर ड्रेन के गांव खांडसा और हीरो होंडा चौक के नजदीक संकरा होने के कारण सेक्टर 33, 34, हीरो होंडा चौक पर जलभराव हो जाता है। दिल्ली-जयपुर हाइवे पानी में डूब जाता है। पिछले साल यहां पर महाजाम भी लग गया था। ड्रेन को दस मीटर चौड़ा किया जाना है। हुडा ने ड्रेन के चौड़ीकरण के रास्ते में आने वाले मकान व अन्य स्ट्रक्चर हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को सिरे चढ़ाने में वक्त लगेगा, जिससे अगले साल ही जलभराव से राहत मिल पाएगी।

बारिश में डूब जाते हैं इलाके

- **डीएलएफ क्षेत्र** : नए शहर के इलाकों को बरसाती पानी से बचाने के लिए डीएलएफ नाला बनाया गया था। लेकिन अतिक्रमण और कब्जे होने के कारण नाले का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। बादशाहपुर नाले पर भी कई जगह पर कब्जा हो चुका है।
- **ग्वाल पहाड़ी** : ग्वाल पहाड़ी नाले पर कब्जे का मामला एनजीटी तक पहुंच चुका है। इस नाले पर कई बिल्डरों ने कब्जा कर इसकी चौड़ाई को कम कर दिया है। ऐसे में नालों के संकरा होने के कारण आसपास की सोसायटी में जलभराव हो जाता है।
- **खांडसा रोड** : इस रोड पर स्थित बरसाती नाले पर जगह-जगह स्थाई कब्जा हो चुका है। जहां पर कब्जा नहीं है वहां पर नाला गंदगी से अटा हुआ है। बारिश के दिनों में इस क्षेत्र के आसपास जलभराव होने से लोगों को परेशानी होती है।
- **चकरपुर नाला** : डीएलएफ सहित नए गुरुग्राम के कई क्षेत्रों को बारिश की आफत से बचाने के लिए नाला बनाया गया था। इस नाले पर भी पिछले कई सालों से अतिक्रमण हो रखा है। जगह-जगह बीच में नाले का अस्तित्व ही खत्म हो चुका है। नाले की सफाई करवाने की भी जरूरत है।
- **ओल्ड डीएलएफ** : ओल्ड डीएलएफ से बजघेड़ा तक इस नाले की लंबाई थी। लेकिन अब यह नाला जगह-जगह कब्जा होने के कारण खत्म हो चुका है। अतिक्रमण होने के कारण यह नाला सिमट गया है।

मर्ज बढ़ता ही गया, ज्यों ज्यों दवा की हमने...

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : मर्ज बढ़ता गया, ज्यों-ज्यों दवा की। यही हाल हो गया राजधानी में जलभराव की समस्या का। दो साल पहले तक जहां डेढ़ सौ जगहों पर जलभराव होता था वो दायरा बढ़कर 370 जगहों तक फैल चुका है। इससे सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि समस्या किस कदर विकराल रूप धारण करती जा रही है। खुद, उपराज्यपाल ने तीन दिन पूर्व सिविक एजेंसियों संग बैठक में प्राथमिकता के आधार पर जलभराव वाली जगहों पर जलनिकासी की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं।

हाल-ए-बयां

- **जहां पहले 150 जगहों पर जलभराव होता था, अब 370 जगह पर होता है**
- **जलभराव की वजह से लगने वाले जाम में हर साल करोड़ों स्वाहा**

सर्वे में सामने आया दर्द

बारिश की वजह से जलभराव सिर्फ सड़कों पर यातायात की समस्या नहीं है, बल्कि इससे देश का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) भी प्रभावित होता है। गैर सरकारी संगठन द्वारा गत वर्ष मानसून के दौरान किए गए एक सर्वेक्षण में कहा गया है कि जलभराव से लोग घंटों जाम में फंसे रहते हैं, जिससे उत्पादक घंटों का नुकसान होता है। लोकल सर्किल्स के अनुसार दिल्ली के 78 फीसद नागरिकों ने सर्वे में माना कि जलभराव की वजह से उनका काफी समय बर्बाद होता है जिससे काम के घंटों का नुकसान होता है। यह सर्वेक्षण महानगरों में किया गया जिससे समस्या की गंभीरता के बारे में जाना जा सके। सर्वेक्षण में कहा गया है कि सरकार को यह समझना होगा कि जलभराव से जीडीपी और जीएसडीपी पर सीधा असर होता है।

सर्वेक्षण में कहा गया है कि कुप्रबंधन की वजह से इतनी बड़ी संख्या में कार्यालय का काम प्रभावित होता है। ऐसे में केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर एकीकृत रुख के साथ काम करना चाहिए। नागरिकों ने जलभराव की समस्या के हल के लिए कई सुझाव दिए हैं। इनमें पॉलीथिन पर प्रतिबंध, गड्ढों को भरना, सब-वे पर टूटे हिस्सों को दुरुस्त करना और नालियों में कूड़ा फेंकने पर प्रतिबंध भी शामिल है। आम लोगों के अलावा कारोबारी गतिविधियां भी जलभराव की वजह से ठप्प हो जाती है। पुरानी दिल्ली की ही बात करें तो चांदनी चौक, सदर बाजार, कश्मीरी गेट, मोरी गेट, खारी बावली, जामा मस्जिद, नई सड़क, चावड़ी बाजार आदि बाजारों का बुरा हाल हो जाता है।

इन बाजारों में सीवर व्यवस्था खराब होने की वजह से सड़कों और गलियों में पानी भर जाता है। अगर बारिश तेज हो गई तो गंदा पानी उनकी दुकानों तक में घुसने लगता है। हालात यहां तक ही खराब नहीं होते। बारिश बंद भी हो जाए तो बाजारों में घंटों पानी भरा रहता है और जब पानी उतर जाता है तो जगह-जगह कीचड़ के ढेर नजर आने लग जाते हैं।

अतिक्रमण का इलाज हो तो राहत मिले

जासं, गाजियाबाद : गाजियाबाद में 80 फीसद इलाकों में नाली-नाले अतिक्रमण की भेंट चढ़ चुके हैं। इससे बारिश के दिनों में जल निकासी बड़ी समस्या बनकर सामने आती है। समय समय पर नगर निगम व जीडीए द्वारा अतिक्रमण के लिए अभियान चलाया जाता है, लेकिन इसे ठीक से फालोअप नहीं किया जाता है। यही वजह है कि अभियान के कुछ ही दिनों में स्थिति जस की तस हो जाती है। शहर की शायद ही ऐसी कोई कॉलोनी होगी जहां यह समस्या न हो। जलभराव का एक और प्रमुख कारण हर तरफ पक्का निर्माण है। पार्क हो या फुटपाथ सभी स्थानों को पक्का बना दिया गया है।

बारिश का पानी सड़क घंटों भरा रहता है। यहां तक कि पेड़ों के आसपास भी पक्का निर्माण कर दिया गया है। यह समस्या तभी दूर हो सकती है जब जगह जगह पर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए जाएं। और जल भराव वाले स्थान पर कुछ कच्ची जमीन छोड़ी जाए। इसके अलावा शहर के नालों व नालियों के ऊपर से अतिक्रमण हटाया जाए। इस समस्या के निराकरण के लिए लगातार अभियान चलाया जा और उसका फालोअप किया जाए। इस साल भी अभी तक शहर के नाली-नालों को अतिक्रमणमुक्त नहीं कराया जा सका है। बारिश में फिर से शहरवासियों को दिक्कत हो सकती है।

जलभराव से रुक जाता है ट्रैफिक, लगता है जाम : बारिश के बाद शहर में कई स्थानों पर जाम लग जाता है। ट्रैफिक सिस्टम फेल हो जाता है।

यहां-यहां लग जाता है जाम : इससे मोहननगर, कौशांबी, इंदिरापुरम, यूपी गेट, जीटी रोड राजेंद्र नगर, मेरठ तिराहा, गौशाला अंडरपास अंबेडकर रोड, रमतेराम रोड, मालीवाड़ा, एनएच-58, राजनगर एक्सटेंशन समेत शहर के अन्य कई क्षेत्रों में जाम लग जाता है।

नगर निगम के इंतजाम

5 पंपिंग सेट
50 सफाई कर्मचारी

जलभराव के प्वाइंट

- मेरठ तिराहा • गौशाला अंडर पास
- जीटी रोड राजेंद्र नगर
- शालीमार गार्डन 80 फुटा रोड
- शहीदनगर • कौशांबी
- इंदिरापुरम साइटफोर औद्योगिक क्षेत्र
- पटेल नगर • मालीवाड़ा • बागू
- सुदामापुरी • नंदग्राम
- मरियमनगर • नवयुग मार्केट
- गोविंदपुरम
- राजनगर एक्सटेंशन चौराहा

हेल्पलाइन नंबर 18001803012 नगर निगम में पांचवें तल पर बनाया गया कंट्रोल रूम